

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2016/ज्येष्ठ 26 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 65]
No. 111]	DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2016/JYAISTHA 26, 1938	[N.C.T.D. No. 65]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जून, 2016

2016 का विधेयक संख्या 03

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का 3) में पुनः संशोधन के लिए

एक

विधेयक

सं. 21(26)डीवैट (ए)/2016/वि.स.स.-VI/वि./3253.—इसे भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाएगा :-

- लघु शीर्षक, विस्तार तथा प्रारंभ :—(i) यह अधिनियम दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा।
(ii) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।
(iii) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तिथि से लागू होगा :
इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए भिन्न-भिन्न तिथियां निश्चित की जा सकती है।
- धारा 3 का संशोधन — दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 में, उप-धारा (10) के बाद, निम्न उप-धारा को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :—
“(11) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे सामानों को निर्दिष्ट कर सकती है जिस पर व्यक्त को सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर अग्रिम कर का भुगतान करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत उस सामान पर लागू कर की दरें उन दरों से अधिक नहीं होगी जो भारत के बाहर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली में ऐसे सामान का आयात करने पर है अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अन्तर्गत लागू होती है। भुगतान किए गए कर की गणना कर देने वाले व्यक्ति के अंतिम कर दायित्व में की जायेगी।

बशर्ते कि सरकार अधिसूचना जारी कर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अग्रिम रूप से कर भुगतान की छूट या अग्रिम में कर के भुगतान की दर को कम कर सकती है जैसाकि अधिसूचना की शर्तों में निहित है :

इसके अलावा बशर्ते कि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी मामले के सभी पहलुओं की जांच के बाद इस निर्णय पर पहुँचता है कि इस व्यक्ति को अग्रिम रूप से कर भुगतान से छूट दी जा सकती है या इस व्यक्ति को अग्रिम रूप से कर के भुगतान की दर में छूट दी जा सकती है, तो वह ऐसा कर सकता है और उस व्यक्ति पर ऐसी निबंधन एवं शर्तें लगा सकता है जो उसके अनुसार सही हैं।

स्पष्टीकरण :- जो व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सामान का आयात करेगा, उसे इस धारणा के आधार पर अग्रिम कर का भुगतान करना होगा कि ऐसे सामान बिक्री या निर्माण में प्रयोग हेतु या बिक्री के लिए वस्तु बनाने हेतु मंगवाई गई है अन्यथा उस व्यक्ति को सिद्ध करना होगा कि ऐसी वस्तु या इनसे निर्मित कोई उत्पाद खरीद एवं आयात मूल्य से कम दर पर नहीं बेचा जाएगा "

3. **धारा 29 का संशोधन** — मूल अधिनियम की धारा 29 में उप-धारा (1) के बाद तथा स्पष्टीकरण 1 से पूर्व, निम्न उप-धारा शामिल की जाती है :-

"(2) आयुक्त सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी डीलर या डीलरों के वर्ग को निर्धारित तिथि से डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से रिटर्न भरने को कह सकता है।"

4. **नई धारा को शामिल करना** — मूल अधिनियम की धारा 50 के बाद निम्नलिखित नई धारा शामिल की जायेगी:-

"50क बिक्री सूचना का इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनीकेशन —(1) सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी डीलर या डीलरों के वर्ग को ऐसे फीजिकल डिवाइज का अनुपालन या सॉफ्टवेयर आवश्यक कर सकता है जोकि आयुक्त को बिक्री इनवाइस की सूचना के तत्काल संचार के लिए आवश्यक है।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत अपेक्षित डिवाइस या सॉफ्टवेयर के उपकरण या स्थापना की लागत डीलर द्वारा वहन की जाएगी।"

5. **धारा 86 का संशोधन** — मूल अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (10) में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

6. **नई धारा को सम्मिलित करना** — मूल अधिनियम में धारा 91 के बाद, निम्न धारा सम्मिलित की जाएगी, अर्थात् :-

"91 क विशेष न्यायालय और लोक अभियोजक —(1) इस अधिनियम में कुछ भी प्रतिकूल होते हुए भी, यदि सरकार चाहे तो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शीघ्र या आवश्यक इस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमों के उद्देश्यों से दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से विशेष अदालत स्थापित कर सकती है।

(2) विशेष अदालत के लिए सरकार लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक से अधिक व्यक्ति को अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।"

7. **धारा 92 का संशोधन** —मूल अधिनियम की धारा 92 में उप-धारा (2) के बाद निम्न उप-धारा सम्मिलित की जाएगी, अर्थात् :-

(3) प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति जो प्राधिकृत है, अपराध की जांच के बाद अभियोजन स्वीकृत या अन्यथा सिफारिशों के साथ आयुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और फिर निर्णय लेगा कि इस मामले में अभियोजन अनिवार्यतः अपेक्षित है और यदि है तो प्राधिकृत अधिकारी अधिकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के समक्ष या सरकार द्वारा नामित विशेष न्यायालय के समक्ष इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत करेगा।"

8. **धारा 93 का संशोधन** — मूल अधिनियम की धारा 93 की उप-धारा (1) में निम्न परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

"उपबंध है कि एक ही प्रकृति के पुनः या उत्तरवर्ती अपराध के मामले में समझौता लागू नहीं होगा "

9. **धारा 107 का संशोधन** — मूल अधिनियम की धारा 107 में "अधिनियम के अंतर्गत शब्द सिम्बॉल तथा डिजिट के लिए अप्रैल 2013 के प्रथम दिन से पूर्व किसी अवधि की समाप्ति के लिए अधिनियम की धारा 32 या धारा 33 के अंतर्गत पहले से निर्धारित शब्द एवं सिम्बॉल के लिए, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार ऐसी मुख्य स्कीम को प्रारंभ करने से पूर्व कम से कम एक वर्ष की अवधि से पूर्व" प्रतिस्थापित होगा।

उद्देश्य एवं कारणों का विवरण

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के तहत संशोधन का प्रस्ताव है कुछ विनिर्दिष्ट प्रावधानों को सम्मिलित किया जा सके जिससे विभाग या समय समय पर इसके स्टैकहोल्डरों द्वारा नोटिस की गई विसंगतियों/असंगति को दूर किया जा सके, ताकि जनहित में कुछ अपेक्षित परिवर्तन के लिए कर प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके।

धारा 3, में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य भारत से बाहर से सामान आयात करने वाले व्यक्ति से अग्रिम कर की वसूली एवं संग्रहण का प्रावधान करना और आयातकर्ता द्वारा कर की चोरी की संभावना को न्यूनतम करना और कर प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाना है ।

धारा 29 में प्रस्तावित संशोधन से डिजीटल हस्ताक्षर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक विकल्प के माध्यम से रिटर्न फाईल करने में सुविधा होगी अतः विभाग में व्यक्तिगत रूप से डीवेट 56 फार्म फाईल करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

नई धारा 50क को सम्मिलित करने का उद्देश्य , इलेक्ट्रॉनिक संचार तंत्र के माध्यम से डीलरों द्वारा की गई बिक्री का डेटा प्राप्त करना और इस प्रकार कर की चोरी को रोकने की दिशा में किसी बिक्री डेटा में हेराफेरी के विकल्प को नगण्य करना है ।

धारा 86 के संशोधन में प्रस्तावित है कि कर कमी से संबंधित रिटर्न में गलत, झूठी या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर जुर्माना की राशि को 10,000/—रु. से कम कर 1,000/—रु. करना ताकि 100/—रु. या उससे कम की कर कमी पर 10,000/—रु. का भारी जुर्माना न लगे ।

नई धारा 91 को शामिल करने का प्रस्ताव अपराधों पर जल्द मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु समक्ष बनाने के प्रावधान के लिए है ।

धारा 92 का संशोधन का प्रस्ताव है ताकि अपराध की जांच के बाद अभियोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विकल्प की प्रक्रिया को सम्मिलित करना ।

धारा 93 में संशोधन का प्रस्ताव आदतन अपराधियों के अपराधों की पुनरावृत्ति को समाप्त करने के लिए है।

धारा 107 के संशोधन का उद्देश्य है, सर्वक्षमता स्कीम से संबंधित प्रावधानों को प्रारंभ करना ताकि भविष्य में अधिनियम के संशोधन के बिना ऐसी स्कीम प्रारंभ करना ताकि भविष्य में अधिनियम के संशोधन के बिना ऐसी स्कीम प्रारंभ की जा सके।

बिल का उद्देश्य है उपरोक्त उद्देश्यों को हासिल करना।

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 में किसी प्रकार की वित्तीय जटिलताएं सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से नये पदों पर कोई खर्च अपेक्षित नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान से संबंधित ज्ञापन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 में निम्नलिखित विषयों को छोड़कर किसी अधिकारी के अधीनस्थ विधान बनाने की शक्तियों के प्रत्यायोजन के विषय में कोई प्रावधान नहीं है।

1. इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन अग्रिम कर के अंतर्गत सामान तथा उसकी दरों को विनिर्दिष्ट करने, इसकी शर्तें तथा अग्रिम कर वसूलने की पद्धति संबंधी प्रत्यायोजन :-
2. अधिनियम की धारा 3 के अधीन डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या अन्य इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रक्रिया से रिटर्न भरने संबंधी अनिवार्यता के विषय में प्रत्यायोजन
3. अधिनियम की धारा 4 के अधीन वस्तुगत अनुपालन उपकरणों या साफ्टवेयर के माध्यम से बिक्री इनवाइस की सूचना तत्काल प्राप्त करने के लिए प्रत्यायोजन।
4. इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन विशेष न्यायालयों के गठन हेतु प्रत्यायोजन ।

प्रसन्ना कुमार सुर्यदेवरा, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th June, 2016

BILL NO. 03 OF 2016

THE DELHI VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (3 of 2005)

No. 21(26)/DVAT(A)/2016/LAS-VI/Leg./3253.—Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.—(i) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Act, 2016

(ii) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(iii) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. Amendment of section 3.—In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 3, after sub-section (10), the following sub-section shall be inserted, namely:-

“(11) Notwithstanding anything contained in this Act to the contrary, the Government may by notification specify the goods on which a person shall pay tax in advance at the rates notified by the Government but not exceeding the rates applicable on such goods under this Act, when he imports such goods into the National Capital Territory of Delhi from a place outside India, subject to such conditions as may be specified in the notification. The aforesaid payment of tax in advance shall be counted towards the final tax liability of the taxable person:

Provided that the Government may by notification exempt any person or class of persons from payment of tax in advance or reduce the rate of payment of tax in advance subject to such conditions as may be notified:

Provided further that if on an application made by a person the Commissioner or an officer authorized by him, after verifying all aspects of the case, arrives at a decision that such person should be exempted from payment of tax in advance or that the rate of payment of tax in advance should be reduce for such person, he may do so and impose such terms and conditions on such person as he may deem fit.

Explanation.—The person, who imports goods into the National Capital Territory of Delhi, shall pay tax in advance, on the presumption that such goods are meant for the purpose of sale or for use in manufacture or processing of goods meant for sale, unless, it is proved otherwise by such person. It is further presumed, unless it is proved otherwise by such person, that such goods or any product manufactured there from shall not be sold below the price at which such goods have been purchased and imported.”.

3. Amendment of section 29.— In the principal Act, in section 29, after sub-section (1), and before the Explanation 1 clause, the following sub-section shall be inserted, namely:-

“(2) The Commissioner may by notification in the official gazette, require any dealer or class of dealers to file the returns only through electronic mode appending digital signatures or any other electronic identification process and with effect from such date as may be specified therein.”.

4. Insertion of new section.—In the principal Act, after section 50, the following new section shall be inserted, namely:-

“**50A Electronic communication of sale information.**—(1) the Government may by notification in the official gazette require any dealer or class of dealers to install such physical compliance devices

or software, as may be considered necessary for instantaneous communication of the information of sale invoices to the Commissioner.

(2) The cost of equipment and installation of the device and software, as may be required under sub-section (1), shall be borne by the dealer.”.

5. Amendment of section 86.- In the principal Act, in section 86, in sub-section (10), for the words “ten thousand rupees”, the words “one thousand rupees” shall be substituted.

6. Insertion of new section.- In the principal Act, after section 91, the following new section shall be inserted, namely:-

“91A Special Courts and Public Prosecutor.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act to the contrary, the Government may, if considers expedient or necessary, constitute, by notification in the Official Gazette, a Special Court with the concurrence of the Chief Justice of the Delhi High Court for the purposes of the trial of offences under this Act.

(2) For the Special Court, the Government shall appoint a person to be the Public Prosecutor and may appoint more than one person to be the Additional Public Prosecutors.”.

7. Amendment of section 92.—In the principal Act, in section 92, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:-

“(3) Every officer or person so authorized shall, upon investigation of the offence, submit a report to the Commissioner with the recommendations for sanctioning prosecution or otherwise and the Commissioner, shall, then take a decision as to whether prosecution is essentially required in the matter and if so, the authorized officer shall launch prosecution before the Metropolitan Magistrate having jurisdiction over the area or before a court specially designated by the government for the purpose.”.

8. Amendment of section 93.—In the principal Act, in section 93, in sub-section (1) the following proviso shall be inserted, namely:-

“ Provided that the composition of offence shall not apply in case of second and subsequent offence of the same nature.”.

9. Amendment of section 107.—In the principal Act, in section 107, for the words, symbols and digits “under the ‘Act’, for any period ending before first day of April, 2013”, the words and symbols “already assessed under section 32 or section 33 of the Act , as the case may be, before a period of at least one year from introduction of such Amnesty Scheme” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Value Added Tax Act, 2004 is proposed to be amended to incorporate some specific provisions which are necessitated by a variety of compulsive reasons varying from – removal of some discrepancies/anomalies noticed by the department or brought to its notice by the stakeholders from time to time, making the tax administration more efficient and for making some changes required in the public interest.

The proposed amendment in section 3 aim at introducing provisions for levy and collection of advance tax from persons importing goods from outside India and to minimize the chances of evasion of tax by importers thereby making the tax administration more efficient.

The proposed amendment in section 29 will facilitate the dealers in filing the returns through digital signatures or other electronic options, thereby dispensing with the requirement of filing Form DVAT 56 in person in the Department.

Insertion of new section 50A aim at capturing the data of sales made by dealers instantly through electronic communication thereby minimizing the chances of manipulation of any sale data afterwards and evasion of tax thereof.

Amendment of section 86 is proposed to reduce the minimum amount of penalty from Rs. 10,000/- to Rs. 1,000/- when furnishing of false, misleading or deceptive information in returns leads to a tax deficiency so that instances of lower tax deficiencies, say Rs. 100/- or even less shall not attract heavy penalty of Rs. 10,000/-.

The proposal for insertion of new section 91A is to make enabling provisions for setting up of Special Courts for speedy trials of the offences.

The proposed amendment of section 92 aims to incorporate the process to be opted by an authorized officer for prosecution after investigation of an offence.

The amendment in section 93 is to disallow compounding of offences to a habitual offender.

Amendment in section 107 aims to make the provisions relating to introduction of Amnesty Scheme generalized so that such a scheme can be introduced any time in future without requiring amendment of the Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Delhi Value Added Tax (Amendment) Bill, 2016 does not involve any additional financial implications since no outgo on new posts is anticipated from the Consolidation Fund of the National Capital Territory of Delhi.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Value Added Tax (Amendment) Bill, 2016 does not make provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation except-

- (i) the delegation under section 2 of this Act for specifying the good and rates of advance tax thereof, terms and conditions and the manner of levy of advance tax.
- (ii) the delegation under section 3 of this Act regarding requirement of filing returns in electronic mode through digital signatures or any other electronic identification process.
- (iii) the delegation under section 4 of this Act for seeking instantaneous information of sale invoices through physical compliance devices or software.
- (iv) the delegation under section 6 of this Act for constitution of Special Courts.

Prasanna Kumar Sryadevara, Secy.